IF UNDELIVERED
PLEASE RETURN TO
मारवाड़ का मित्र
:: Regd. Office ::
वैष्णव फार्म परावा,
जिला - सांचौर (343041)

सांचौर (जालोर) से प्रकाशित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

मारवाड़ का मित्र

होली की शुभकामनाएं

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post Reg No. RJ/SRO/9657/2023-25

Www.MarwadkaMitra.in

प्रकाश वैष्णव -प्रकाशक/संपादक 9602473302

वर्ष 23 | अंक 06 | सांचौर, शनिवार, 15 मार्च 2025 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव, | मूल्य वार्षिक 500 रुपये | कुल पृष्ठ - 4

शुभ होली

हर्ष-उल्लास का यह अनुपम पर्व सर्वत्र खुशहाली व सद्भाव के रंग बिखेरे, इस उम्मीद के साथ सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

पीएफ की ब्याज दरों में कोई बदलाव किया नहीं

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। ईपीएफ जमा पर मिलने वाले ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी ईपीएफओ के अंशदाताओं को 8.25 फीसदी ब्याज मिलता रहेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में ईपीएफ जमा पर 8.25 फीसदी वार्षिक ब्याज दर जमा करने की सिफारिश की गई। अब केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद ईपीएफओ अंशदाताओं के खातों में ब्याज दर जमा जमा कराया जाएगा।

"सहकारिता में निजी क्षेत्र का प्रादुर्भाव" क्या सहकार भावना की सच्चाई केवल घोषणाई ?

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। देश के हर कोने में सहकार भावना जागृत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय निरंतर देश के गृह एवं केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व काल में नए आयाम स्थापित कर रहा हैं, जिसकी कड़ी में पैक्स से लेकर केंद्रीय रजिस्ट्रार तक के कार्यालय को कंप्यूटरीकृत जा रहा है। इसके अलावा 54 प्रकार की अनेक योजनाओं का क्रियावन्यन पैक्स के जरिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा हैं, वही एक ओर केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह निरंतर हर समारोह में सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं के खाते जिला सहकारी बैंकों में खोलने के लिए उद्बोधन दे रहे है। साथ ही, राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ हीरक जयंती समारोह के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने संबोधन में कहा कि "जिला सहकारी बैंकों में कुल 433000 करोड़ रुपए जमा हैं और राज्य सहकारी बैंकों में 2,42,000 करोड़ रूपए जमा हैं और हमें इसमें वृद्धि का लक्ष्य भी तय करना चाहिए" इतना ही नहीं उन्होने कहा था कि सहकारी बैंक की सारी को-ऑपरेटिव्स के बैंक अकाउंट अगर इन सहकारी बैंक में आ जाते हैं तो अपने आप 20 प्रतिशत लो कॉस्ट डिपॉजिट में वृद्धि होगी, जिससे मुनाफा भी अपने आप बढ़ जाएगा और ऋण देने की क्षमता भी बढ़ेगी।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला के दौरान कहा कि सारे खाते कोऑपरेटिव बैंकों में खोलने के लिए भी कोऑपरेशन अमोग्स्त को-ऑपरेटिव्स की शुरूआत की है, इससे सहकारिता के लिए अपने आप धन भी उपलब्ध हुआ है और बैंक भी मजबूत हुए हैं, पर, राजस्थान में सहकारिता का प्रादुर्भाव निजी क्षेत्र में सर्वाधिक दिखाई दे रहा हैं,

पर, राजस्थान में सहकारिता का प्रादुर्भाव निजी क्षेत्र में सर्वाधिक दिखाई दे रहा हैं, हाल ही में नेहरू सहकार भवन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष से संबंधित प्रदेश की वार्षिक कार्ययोजना एवं कैलेण्डर के विमोचन के बाद राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ जयपुर द्वारा राज्य सरकार को 21 लाख 73 हजार रुपये का लाभांश दिया हैं । यह प्रतीकात्मक चेक राज्यपाल, राजस्थान सरकार के नाम 21 लाख 73 हजार 605 रुपये के लाभांश के रुप में सौंपा गया है, यह प्रतीकात्मक चेक एक निजी व्यवसायिक बैंक का बताया जा रहा हैं, जिससे प्रतित हो रहा हैं कि सहकार भावना की सच्चाई केवल घोषणाई हैं, प्रदेश की शीर्ष सहकारी संस्था का व्यवसायिक खाता एक निजी बैंक में चलना सहकारिता की भावना के विरोधाभास को दर्शाता हैं। हालांकि इस मामले को लेकर सहकारिता विभाग से निरंतर संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन विभागीय अधिकारी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष से संबंधित प्रदेश की वार्षिक कार्ययोजना एवं कैलेण्डर के विमोचन के बाद राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान कॉनफैड द्वारा राज्य सरकार को लाभांश का प्रतीकात्मक चेक सुपुर्द करते सहकारिता मंत्री एवं विभागीय अधिकारी

कोलायत केवीएसएस के विवाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया बैंक खातों को डी फीज करने के आदेश

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर । राजस्थान उच्च न्यायालय ने बीकानेर कोलायत क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, बीकानेर से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अपना आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति मुन्नूरी लक्ष्मण की एकल पीठ ने समिति के बैंक खातों को डीफ्रीज करने का निर्देश दिया और यह स्पष्ट किया कि समिति के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) दोनों को संयुक्त रूप से चेक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा। बता दें यह मामला सोसायटी के अध्यक्ष हरिराम द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 19732/2024 से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश के तहत, समिति के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे, जिससे संस्था का वित्तीय संचालन प्रभावित हुआ। याचिका में तर्क दिया गया कि राज्य सरकार के परिपत्र और समिति के प्रस्ताव के अनुसार, चेक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार समिति के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोनों को दिया गया है। हालांकि, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर विवाद के चलते बैंक ने खातों का संचालन रोक दिया था।

न्यायालय के आदेश का प्रभाव

इस निर्णय के बाद, बीकानेर कोलायत क्रय विक्रय सहकारी समिति के वित्तीय लेन-देन फिर से सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगे। यह आदेश सहकारी समितियों के कामकाज और बैंकिंग प्रक्रियाओं में प्रशासनिक दखल को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।

सहकारिता विभाग की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। किसानों की समृद्धि से ही राष्ट्र की प्रगति संभव है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि राज्य की सहकारी समितियों में पारदर्शिता के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। गबन-घोटालों में लिप्त कार्मिकों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। साथ ही, वर्षों से लम्बित प्रकरणों की भी समीक्षा कर उनका निस्तारण किया जा रहा है। सहकारी संस्थाओं के संचालन में पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए नवीन को-ऑपरेटिव कोड लागू करने की कार्यवाही की जा रही है। सहकारिता मंत्री विधानसभा में विभाग की (मांग संख्या-50) अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने सहकारिता विभाग की 18 अरब 48 करोड़ 27 लाख 97 हजार रूपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं। श्री दक ने कहा कि सहकारिता के व्यापक महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। साथ ही, भारत के सहकारी आन्दोलन को मजबूत करने के लिए 'सहकार से समृद्धि' कार्यक्रम की शुरूआत की गई है, जिसे सफल बनाने के लिए सभी का साथ अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए हम कृतसंकल्पित हैं। सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य में सहकारी समितियां बहुउद्देशीय लक्ष्यों की ओर अग्रसर है। राज्य में विभिन्न प्रकार की 42 हजार 352 सहकारी समितियां हैं, जिनमें 1 करोड़ 34 लाख 90 हजार से अधिक सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की खाद, बीज, जुताई और अन्य छोटी-छोटी जरूरतों के लिए राज्य सरकार ने ब्याजमुक्त अल्पकालीन ऋण की सीमा बढ़ाकर 25 हजार करोड़ रुपये करने की घोषणा की है। इसके लिए 768 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान पर व्यय किए जाएंगे। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में आगामी वित्तीय वर्ष में 2.50 लाख गोपालक परिवारों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई है, जिस पर 150 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार अधिक से अधिक पशुपालकों को इस योजना से लाभान्वित करने का प्रयास करेगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत की, जिसके तहत देश के लभगग 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सालाना 6 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाती है। इसी क्रम में राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई, जिसके अंतर्गत देय राशि 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने की घोषणा की गई है। अब राज्य के लगभग 72 लाख किसानों को सालाना 9000 रुपये की राशि मिलने लगेगी। उन्होंने कहा कि योजना में कुछ अनियमितताएं भी सामने आई हैं, जिनमें हमारी पारदर्शी सरकार दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करेगी। श्री दक ने कहा कि सहकारिता की पहुंच राज्य के दूर-दराज क्षेत्र में सुनिश्चित करने के लिए आगामी 2 वर्षों में शेष रही 2500 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी। इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही करते हुए ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना के मापदण्डों का सरलीकरण किया गया है। साथ ही, नवीन 8 जिलों में क्र य-विक्रय सहकारी संघों की स्थापना होगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिए भी राज्य सरकार वचनबद्ध है। इसे मूर्त रूप देने के लिए महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का निर्णय किया है और अब तक 54 नवीन महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन कर दिया गया है। इसमें महिला सदस्यों की हिस्सा राशि भी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। श्री दक ने सदन को अवगत कराया कि प्रदेश में 6781 पैक्स पर कम्प्यूटराइजेशन किया जा चुका है। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकत अन्न भण्डारण योजना के तहत राज्य में नए गोदामों का निर्माण प्रगति पर है। राज्य बजट में 500 मैट्रिक टन क्षमता के 100 एवं 250 मैट्रिक टन क्षमता के 50 नये गोदामों का निर्माण कराये जाने तथा 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जीर्ण-शीर्ण गोदामों के पुनर्निर्माण की भी घोषणा की गई है। इससे राज्य की भण्डार क्षमता में 1.13 लाख मैट्रिक टन की वृद्धि होगी।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसानों की समृद्धि से ही राष्ट्र की प्रगति संभव, किसानों को दिया जाएगा 25 हजार करोड़ रुपये का अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋण, सहकारी समितियों में पारदर्शिता के लिए उठाये जा रहे प्रभावी कदम नवीन को-ऑपरेटिव कोड लागू करने की हो रही कार्यवाही

सहकारिता मंत्री ने कहा कि हमारे कुशल प्रबंधन से किसानों के बीमा प्रीमियम में कमी आई है, जिसका सीधा लाभ किसान भाइयों को हुआ है। वर्ष 2023-24 में किसानों पर डाले गए अतिरिक्त वित्तीय भार की जांच करवाई जा रही है, जिसके बाद संलिप्तता पाए जाने दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 में मूंग, मूंगफली एवं सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर ऐतिहासिक खरीद की है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गत पांच वर्ष में भी इतनी खरीद नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

सभी किसान भाईयों को होली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

घाणा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड घाणा

किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है

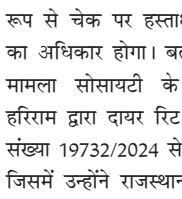

मानसिंह गौड़
अध्यक्ष

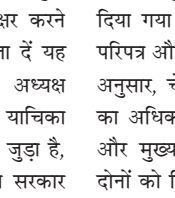

कपूराराम
व्यवस्थापक

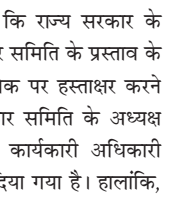

शुभम दवे
स. व्यवस्थापक

हमारी सेवाएं : कस्टम हायरिंग सेंटर - अल्पकालीन फसली ऋण वितरण - खाद-बीज-कीटनाशक विक्रय

ऑडिट नहीं करवाने वाली सहकारी समितियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जनवरी माह की एमपीआर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 613 सहकारी समितियां ऑडिट से शेष एवं 265 सहकारी समितियां बैकलॉग ऑडिट से शेष बताई है

जोधपुर । प्रदेश की सहकारी समितियों में ऑडिट नहीं करवाने पर अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही के लिए सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय ने गत दिनों आदेश जारी कर समस्त क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी सहकारी समितियां खण्डवार निर्देशित किया, जिसके क्रम में जोधपुर क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी प्रशांत कल्ला ने कल विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां जालोर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही एवं जैसलमेर को एक पत्र लिखा हैं। जिसके मुताबिक जनवरी माह की एमपीआर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 613 सहकारी समितियां ऑडिट से शेष एवं 265 सहकारी समितियां बैकलॉग ऑडिट से शेष बताई है। साथ ही, पत्र में बताया गया कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 54 (3) के अनुसार प्रत्येक सोसायटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा उस वित्तीय वर्ष की, जिससे ऐसे लेखे संबंधित है, समाप्ति के छः मास के भीतर-भीतर किए जाने का प्रावधान हैं । लेकिन धारा 54(3) की पालना करने में सहकारी समितियां विफल रही है। वही विशेष लेखा परीक्षकों द्वारा क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी को अवगत कराया जाता रहा हैं कि सहकारी समितियों द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षक को ऑडिट कार्य के लिए रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा हैं, जिस पर संबंधित सहकारी समिति के विरुद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में समितिवार वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश प्रदान करते हुए, सहकारी अधिनियम अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर ऑडिट नही करवाने वाली सहकारी समितियों के विरूद्ध इसी माह में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।

यूएफबीयू के आह्वान पर देश के बैंक कर्मियों ने संसद पर दिया विशाल धरना

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली । संसद भवन के आगे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के आह्वान पर बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने अपनी मांगो को लेकर विशाल संयुक्त धरना देकर सरकार के प्रति विरोध व्यक्त किया हैं । इस दौरान बैंक कर्मचारी नेता सूरजभान सिंह आमेरा ने मंच के माध्यम से कर्मियों की मांगों पर जोशीली नारेबाजी करवाई, वही धरने को ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन के महासचिव सी एच वेंकटचलम, स्त्रक्त के विभिन्न नेताओं सहित विभिन्न राजनीतिक दल के सांसदों ने संबोधित कर बैंक कर्मियों की माँगो का समर्थन किया । साथ ही राजनीतिक दल के सांसदों ने संसद के अन्दर आवाज उठाने का विश्वास दिलाया हैं। इस संबंध में राजस्थान प्रदेश बैंक एम्पलाइज यूनियन के उप महासचिव बैंक कर्मचारी नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने बताया कि बैंको में सभी कैडर के हजारो रिक्त पड़े पदों पर भर्ती करने, आरबीआई, नाबार्ड, बीमा, केंद्र, राज्य कर्मियों के समान बैंकों में पाँच दिन का बैंक कार्य सप्ताह लागू करने, केंद्र व राज्य कर्मियों के समान ग्रेच्युटी भुगतान 25 लाख करने, नियमित बैंक कार्य की आउटसोर्सिंग एवं ठेका प्रथा बंद करने, बैंक शाखाओ में सुरक्षा प्रहरी लगाने, बैंक शाखा में में महिला व स्टाफ को सुरक्षा प्रदान करने, लंबित मुद्दों का समाधान करने, लिखित समझौतों को लागू करने आदि माँगो को लेकर 24 एवं 25 मार्च की दो दिवसीय बैंक हड़ताल से पूर्व आज संसद पर धरना आयोजित किया गया । जिसमें राजस्थान से सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा के साथ महेश शर्मा, आर जी शर्मा, मेघा मलिक, राकेश कुमार गुर्जर, हेमन्त वर्मा, मनीष मीणा, रोशन लाल, महेश मीणा, विनील स सेना, रवीदीप चतुर्वेदी, रविकान्त शर्मा, बनवारी लाल विभिन्न बैंक नेतृत्व के साथ व्यावसायिक एवं सहकारी बैंकों से पाँच सौ बैंक कर्मियों ने दिल्ली धरने में भागीदारी दर्ज करवाई है

एक अधिकारी को एक से अधिक केवीएसएस में व्यवस्थापक पद का कार्यभार नहीं दिए जाने के निर्देश

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । *प्रदेश में राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय सहकारी संघ द्वारा विभिन्न क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से लगातार रबी और खरीफ सीजन में समर्थन मूल्य पर जिंसो की खरीद की जाती हैं, लेकिन सीजन में समर्थन मूल्य पर खरीद के दौरान एक अधिकारी को अन्य क्रय-विक्रय सहकारी समिति का अतिरिक्त कार्यभार देने की स्थिती को लेकर अब सहकारिता विभाग ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में एक अधिकारी को एक से अधिक क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के व्यवस्थापक का कार्यभार नहीं दिया सकता हैं ।*

सीजन में समर्थन मूल्य पर खरीद के दौरान एक अधिकारी को अन्य क्रय-विक्रय सहकारी समिति का अतिरिक्त कार्यभार देने की स्थिती को अब सहकारिता विभाग ने स्पष्ट किया

जिसके क्रम में सहकारिता विभाग संयुक्त शासन सचिव दिनेश कुमार जांगिड़ ने एक कार्यालय आदेश जारी कर उसकी प्रतिलिपी सहकारिता विभाग पंजीयक एवं राजफैड प्रबंध निदेशक सहित समस्त अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, समस्त उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों को भेजकर अक्षरश: पालना सुनिश्चित किए जाने के लिए निर्दशित किया है।

सभी किसान भाईयों को होली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड रतनपुरा

(किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी)

रायमलराम नेहरा
व्यवस्थापक

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है

मोतीराम
अध्यक्ष

देवाराम
उपाध्यक्ष

एवं समस्त संचालक मण्डल सदस्य गण

हमारी सेवाएं : अल्पकालीन फसली ऋण वितरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, राशन वितरण

25 वर्षों से सहकारी समितियों को नहीं मिला लाभांश

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । जिले में सहकारिता की भावना विलोपित होती नजर आ रही हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन के शुरुआती पन्नों में सदस्य सहकारी समितियों को लाभांश देने के शब्द नजर आते हैं, लेकिन अंत तक पहुंचते ही वह गायब हो जाते हैं । एक ओर सीसीबी की वार्षिक आमसभा में विचारणीय विषय पर पिछले 13 साल से बिन्दु संख्या 7 के तहत सदस्य सहकारी समितियों को लाभांश वितरण पर विचार किया जाता हैं, लेकिन लाभांश का वितरण नहीं होने से बैंक वार्षिक प्रतिवेदन में उल्लेखित लाभांश की राशि के लिए सदस्य सहकारी समितियां पिछले 13 साल से तरस रही है। वही संपूर्ण प्रतिवेदन में विचारणीय विषय के अलावा अन्य कई पर भी लाभांश शब्द का उल्लेख तक नहीं मिल पाता हैं । दूसरी ओर सहकारिता में यह प्रावधान हैं कि जो सहकारी संस्था वित्तीय वर्ष में लाभ अर्जित करती हैं, उसे अपने सकल लाभ में से कुछ हिस्सा संबंधित सदस्य को लाभांश के तौर पर वितरित करना होता है। जहां जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक वित्तीय वर्ष 2000-01 के बाद निरंतर लाभ अर्जित कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में हिस्सा पूंजी 3778.64 लाख, कार्यशील पूंजी 103251.51 लाख सहित संचित लाभ 439.49 लाख रुपए बताया जा रहा है। लेकिन बैंक की ओर से पिछले 25 सालों से एक भी सदस्य सहकारी समिति को लाभांश की फूटी कौड़ी तक वितरित नहीं हो पाई है।

सीसीबी 25 वर्षो से निरंतर अर्जित कर रही लाभ, आमसभा में केवल खानापूर्ति के तौर पर लिखा जाता लाभांश वितरण करने पर विचार का शब्द, वही सूत्रों ने गत दिनों सहकारिता विभाग प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिखकर बैंक की धारा -55 में उठा रखी जांच की मांग

नाममात्र की ऋण राशि का वितरण

प्रदेश की भाजपा सरकार ने पांच लाख नए किसान सदस्य को ब्याज मुक्त योजना के तहत अल्पकालीन फसली ऋण वितरण योजना के माध्यम से पिछले वित्तीय वर्ष में बजट घोषणा कर सहकारी साख संरचना से जोड़ने का लक्ष्य रखा, लेकिन जिले में केंद्रीय सहकारी बैंक के पास वित्तीय सक्षमता का अभाव होने का ढिंढोरा पीट कर बजट अनुसार ऋण देने की बात सुनाई दे रही हैं । पिछले दो सालों से केवल गिनी चुनी कृषि ऋणदात्री सोसायटी में बड़ी मुश्किल से 1.50 लाख की एमसीएल स्वीकृत वाले नए किसान को मात्र 12 से 15 हजार तक की राशि मुहैया करवाई गई है।

धारा-55 में जांच के मामले पर नहीं लिया संज्ञान

केंद्रीय सहकारी बैंक में स्क्रीनिंग फर्जीवाड़े के अलावा बैंक डीपीसी कमेटी में बरती शिथिलता एवं ऋण माफी योजना में जमकर हुई अनियमितताओं तथा बैंक कार्मिकों के 14, 15, 16वें वेतन समझौते सहित बैंक में मनमाने तरीके से लाखों की खरीद के प्रकरण में सूत्रों ने सहकारिता विभाग प्रमुख शासन सचिव श्रीमति मंजू राजपाल को पत्र लिखकर केंद्रीय सहकारी बैंक स्तर की जांच राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के तहत करवाने की मांग उठाई। लेकिन इस प्रकरण पर प्रमुख शासन सचिव सहकारिता विभाग ने भी कोई संज्ञान नहीं लेने से ऐसा प्रतित हो रहा है कि चांदी के खनकते चंद सिक्कों के आगे सहकारिता विभाग के उच्च स्तर पर बैठे अधिकारियों की सोचने एवं समझने की शक्ति क्षीण हो गई है और केवल दिख रहा है तो "पैसा ही पैसा"! जो बड़े ही चिंता और खेद का विषय है।

सभी किसान भाईयों को होली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

मोतीराम
अध्यक्ष

देवाराम
उपाध्यक्ष

एवं समस्त संचालक मण्डल सदस्य गण

रायमलराम नेहरा
व्यवस्थापक

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है

हमारी सेवाएं : अल्पकालीन फसली ऋण वितरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, राशन वितरण

कृषि को छोड़ खनन, विनिर्माण और अन्य सभी क्षेत्रों में खराब रहा प्रदर्शन

एक तरफ देश की आर्थिक वृद्धि दर के ताजा आंकड़े, तो दूसरी ओर शेयर बाजार में भारी उथल-पुथल से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चिंता की लहरें साफ देखी जा सकती हैं। हालांकि वृद्धि दर को लेकर आर्थिक विशेषज्ञों की ओर से जो अनुमान जाहिर किए गए थे, उसमें ज्यादा फासला नहीं है, फिर भी इसकी निम्न दर ने अर्थव्यवस्था के मामले में सरकार के अक्सर किए जाने वाले दावों को आईना दिखाया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर घट कर 6.2 फीसद रह गई। चिंता का मुद्दा यह भी है कि कृषि को छोड़ कर खनन, विनिर्माण और अन्य सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन खराब रहा। दरअसल, इसी वजह से आर्थिक वृद्धि दर में भी सुस्ती आई है। यों इस बात पर राहत महसूस की जा रही है कि चूंकि पिछली तिमाही यानी जुलाई-सितंबर, 2024 में वृद्धि दर 5.6 फीसद रही थी, इसलिए उसके बाद वाली तिमाही के आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था के रफतार पकड़ने के सूचक हैं। मगर सुधार का आकलन समूचे वित्त वर्ष के आंकड़े के आधार पर ही किया जा सकता है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में अक्तूबर-दिसंबर की तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 9.5 फीसद बताई गई थी। यानी पिछले वर्ष की समान तिमाही में एक साल के भीतर इतना बड़ा फासला यह बताने के लिए काफी है कि देश की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा में सुधार के लिए अभी बहुत ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। एनएसओ के ताजा आंकड़े आने से पहले चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर का दूसरा अनुमान जारी करते हुए इसके 6.5 फीसद रहने का अनुमान जताया गया था। इस लिहाज से देखें तो वृद्धि दर कमोबेश आसपास रही। मगर इसके समांतर खनन और उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि दर तीसरी तिमाही में एक वर्ष पहले के 4.7 फीसद से घट कर 1.4 फीसद रह गई। इसके अलावा, निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, व्यापार, होटल, परिवहन, वित्तीय, जमीन-जायदाद कारोबार, पेशेवर सेवाएं, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं में भी वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई। यों इस तिमाही में कृषि क्षेत्र में उत्पादन 5.6 फीसद बढ़ने को राहत के तौर पर देखा जा सकता है। अफसोस की बात यह है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कई तरह की जटिलताओं के अनुमान पहले से मौजूद रहने के बावजूद सरकार उससे पार पाने के वैकल्पिक इंतजामों पर गौर करने की पर्याप्त कोशिश नहीं करती है। अगर अक्तूबर-दिसंबर के त्योहारी मौसम में भी वृद्धि दर संतोषजनक नहीं रहे तो इससे यही पता चलता है कि आर्थिक विकास के संदर्भ में सरकार के दावे चाहे जो रहे हों, मगर जमीनी स्तर पर चिंता को कम करने की कोशिशें आधी-अधूरी हैं। दूसरी ओर, वस्तुओं पर शुल्क लगाए जाने के मसले पर अमेरिका की नई नीतियों की घोषणा के बाद व्यापार युद्ध की आशंका के बीच दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई। इसके दबाव में भारत के घरेलू शेयर बाजार का मानक सूचकांक 1414 और निफटी 420 अंक टूट गया। इस तेज गिरावट से निवेशकों को नौ लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। स्वाभाविक ही आर्थिक वृद्धि दर के ताजा आंकड़े को शेयर बाजार में गिरावट से जोड़ कर देखा जा रहा है। दुनिया फिलहाल जिस आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, उसमें भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए पूर्व तैयारी करने की जरूरत है।

नीरस होती, होली की मस्ती, रंग-गुलाल लगाया और हो गई होली

-प्रियंका सौरभ
(यह लेखक के अपने विचार है)

पहले की होली और आज की होली में अंतर आ गया है, कुछ साल पहले होली के पर्व को लेकर लोगों को उमंग रहता था, आपस में प्रेम था। किसी के भी प्रति द्वेष भाव नहीं था। आपस में मिल कर लोग प्रेम से होली खेलते थे। मनोरंजन के अन्य साधानों के चलते लोगों की परंपरागत लोक त्यौहारों के प्रति रुचि कम हुई है। इसका कारण लोगों के पास समय कम होना है। होली आने में महज कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन शहर में होली के रंग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। एक माह तो दूर रहा अब तो होली की मस्ती एक-दो दिन भी नहीं रही। मात्र आधे दिन में यह त्योहार सिमट गया है। रंग-गुलाल लगाया और हो गई होली। जैसे-जैसे परंपराएं बदल रही हैं, रिश्तों का मिठास खत्म होता जा रहा है।

होली एक ऐसा रंगबिरंगा त्योहार है, जिसे हर धर्म के लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते रहे हैं। होली के दिन सभी बैर-भाव भूलकर एक-दूसरे से परस्पर गले मिलते थे। लेकिन सामाजिक भाईचारे और आपसी प्रेम और मेलजोल का होली का यह त्योहार भी अब बदलाव का दौर देख रहा है। फाल्गुन की मस्ती का नजारा अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। कुछ सालों से फीके पड़ते होली के रंग अब उदास कर रहे हैं। शहर के बुजुर्गों का कहना है कि ' न हंसी- ठिठोली, न हुड़दंग, न रंग, न ढप और न भंग' ऐसा क्या फाल्गुन? न पानी से भरी 'खेळी' और न ही होली का .....रे का शोर। अब कुछ नहीं, कुछ घंटों की रंग-गुलाल के बाद सब कुछ शांत। होली की मस्ती में अब वो रंग नहीं रहे। आओ राधे खेला फाग होली आई.... ताम्बा पीतल का मटका भरवा दो...सोना रुपाली लाओ पिचकारी...के स्वर धीरे धीरे धीमे हो गए हैं। फाल्गुन लगते ही होली का हुड़दंग शुरू हो जाता था। मंदिरों में भी फाल्गुन आते ही 'फाग' शुरू हो जाता था। होली के लोकगीत गूंजते थे। शाम होते ही ढप-चंग के साथ जगह-जगह फाग के गीतों पर पारंपरिक नृत्य की छटा होली के रंग बिखेरती थी। होली खेलते समय पानी की खेली में लोगों को पकडक़र डाल दिया जाता था। कोई नाराजगी नहीं, सब कुछ खुशी-खुशी होता था। वसन्त पंचमी से होली की तैयारियां करते थे। चौराहो पर समाज के नोहरे व मंदिरों में चंग की थाप के साथ होली के गीत गूंजते। रात को चंग की थाप पर गैर नृत्य का आकर्षण था। बाहर से फाल्गुन के गीत व रसिया गाने वाले रात में होली की मस्ती में गैर नृत्य करते थे। पहले की होली और आज की होली में अंतर आ गया है, कुछ साल पहले होली के पर्व को लेकर लोगों को उमंग रहता था, आपस में प्रेम था। किसी के भी प्रति द्वेष भाव नहीं था। आपस में मिल कर लोग प्रेम से होली खेलते थे। मनोरंजन के अन्य साधानों के चलते लोगों की परंपरागत लोक त्यौहारों के प्रति रुचि कम हुई है। इसका कारण लोगों के पास समय कम होना है। होली आने में महज कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन शहर में होली के रंग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। एक माह तो दूर रहा अब तो होली की मस्ती एक-दो दिन भी नहीं रही। मात्र आधे दिन में यह त्योहार सिमट गया है। रंग-गुलाल लगाया और हो गई होली। जैसे-जैसे परंपराएं बदल रही हैं, रिश्तों का मिठास खत्म होता जा रहा है। जहां तक होली का सवाल है तो अब मोबाइल और इंटरनेट पर ही 'हैप्पी होली' शुरू होती है और खत्म हो जाती है। अब पहले जैसा वो हर्षोल्लास नहीं रह गया है। पहले बच्चे टोलियां बनाकर गली-गली में हुड़दंग मचाते थे। होली के 10-12 दिन पहले ही मित्रों संग होली का हुड़दंग और गली-गली होली का चंदा इकट्ठा करना और किसी पर बिना पूछे रंग उड़ेल देने से एक अलग प्यार दिखता था। इस दौरान गाली देने पर भी लोग उसे हंसी में उड़ा देते थे। अब तो लोग मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। पहले परायों की बहू-बेटियों को लोग बिल्कुल अपने जैसा समझते थे। पूरा दिन घरों में पकवान बनते थे और मेहमानों की आवभगत होती थी। अब तो सबकुछ बस घरों में ही सिमट कर रह गया है। आजकल तो मानों रिश्तों में मेल-मिलाप की कोई जगह ही नहीं रह गई हो। मन आया तो औपचारिकता में फोन पर हैप्पी होली कहकर इतिश्री कर लिए। अब रिश्तों में वह मिठास नहीं रह गया है। यही वजह है कि लोग अपनी बहू-बेटियों को किसी परिचित के यहां जाने नहीं देते। पहले घर की लड़कियां सबके घर जाकर खूब होली की हुल्लड़ मचाती थीं। अब माहौल ऐसा हो गया है कि यदि कोई लड़की किसी रिश्तेदार के यहां ही ज्यादा देर तक रुक गई तो परिवार के लोग चिंतित हो जाते हैं कि क्यों इतना देर हो गया। तुरंत फोन करके पूछने लगते हैं कि क्या कर रही हो, तुम जल्दी घर आओ। क्यों अब लोगों को रिश्तों पर भी उतना भरोसा नहीं रह गया है। दूसरी ओर, होली के दिन खान-पान में भी अब अंतर आ गया है। गुझिया, पूड़ी-कचौड़ी, आलू दम, महजूम (खोवा) आदि मात्र औपचारिकता रह गई है। अब तो होली के दिन भी मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड जैसी चीजों को परोसा जाने लगा है। वहीं, होलिका के चारों तरफ सात फेरे लेकर अपने घर के सुख शांति की कामना करना, वो गोबर के विभिन्न आकृति के उपले बनाना, दादी-नानी का मखाने वाली माला बनाना, रंग-बिरंगे ड्रेसअप में अपनी सखी-सहेलियों संग घर-घर मिठाई बांटना, गेहूं के पौधे भूनना और होली के लोकगीतों को गाना। अब यह सब परंपराएं तो मानो नाम की ही रह गई हैं। होली रोपण के बाद से होली की मस्ती शुरू हो जाती थी। छोटी बच्चियां गोबर से होली के लिए वलुडिये बनाती थी। उसमें गोबर के गहने, नारियल, पायल, बिछियां आदि बनाकर माला बनाती थी। अब यह सब नजर नही आता है। होली से पूर्व घरों में टेशु व पलाश के फूलों को पीस कर रंग बनाते थे। महिलाएं होली के गीत गाती थी। होली के दिन गोठ भी होती थी जिसमें चंग की थाप पर होली के गीत गाते थे। होली रोपण से पूर्व बसंत पंचमी से फाग के गीत गूंजने लगते थे। आज के समय कुछ मंदिरों में ही होली के गीत सुनाई देते हैं। होली के दिन कई समाज के लोग सामूहिक होली खेलने निकलते थे। साथ में ढोलक व चंग बजाई जाती थी, अब वह मस्ती-हुड़दंग कहां? अब होली केवल परंपरा का निर्वहन रह गया है। हाल के समय में समाज में आक्रोश और नफरत इस कदर बढ़ गई है कि सभ्रांत परिवार होली के दिन निकलना नहीं चाहते हैं। लोग साल दर साल से जमकर होली मनाते आ रहे हैं। इस पर्व का मकसद कुरीतियों व बुराइयों का दहन कर आपसी भाईचारा को कायम रखना है। आज भारत देश मे समस्यायों का अंबार लगा हुआ है। बात सामाजिक असमानता की करें, इसके कारण समाज में आपसी प्रेम, भाईचारा, मानवता, नैतिकता खत्म होती जा रही हैं। कभी होली पर्व का अपना अलग महत्व था, होलिका दहन पर पूरे परिवार के लोग एक साथ मौजूद रहते थे। और होली के दिन एक दूसरे को रंग लगा व अबीर उड़ा पर्व मनाते थे। लोगों की टोली भांग की मस्ती में फगुआ गीत गाते व घर-घर जाकर होली का प्रेम बांटते थे।

अब हालात यह है कि होली के दिन 40 फीसदी आबादी खुद को कमरे में बंद कर लेती है। हर माह, हर ऋतु किसी न किसी त्योहार के आने का संदेसा लेकर आती है और आए भी क्यों न, हमारे ये त्योहार हमें जीवंत बनाते हैं, ऊर्जा का संचार करते हैं, उदास मनों में आशा जागृत करते हैं। अकेलेपन के बोझ को थोड़ी देर के लिए ही सही, कम करके साथ के सलोने अहसास से परिपूर्ण करते हैं, यह उत्सवधर्मिता ही तो है जो हमारे देश को अन्य की तुलना में एक अलग पहचान, अस्मिता प्रदान करती है। होली पर समाज में बढ़ते द्वेष भावना को कम करने के लिए मानवीय व आधारभूत अनिवार्यता की दृष्टि से देखना होगा।

लेखक (रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार)

2025-26 बजट

सहकारिता सेक्टर को सुदृढ बनाने के लिए कई उल्लेखनीय घोषणाएं

- किसान सम्मान निधि योजना में 2000 रुपये की जगह 3000 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी
- 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा
- 2.50 लाख अतिरिक्त गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, राज्य सरकार का वर्ष 2025-26 का बजट आपणों अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार करने वाला है। समाज के हर वर्ग के कल्याण की मंशा के साथ लाये गए इस बजट में सहकारिता सेक्टर को सुदृढ बनाने के लिए कई उल्लेखनीय घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की किसान हितेषी सोच को दृष्टिगत रखते हुए बजट में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को अब 2000 रुपये की जगह 3000 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। साथ ही, गेहूं खरीद पर बोनस की राशि बढ़ाकर 150 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। इन घोषणाओं से किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा। वहीं, फसली ऋण का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके ब्याज अनुदान पर 768 करोड़ रुपये व्यय होंगे। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का भी दायरा बढ़ाते हुए 2.50 लाख अतिरिक्त गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं, दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं अकृषि सेक्टर के लिए 400 करोड़ रुपये के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की घोषणा की गई है। ये सभी घोषणाएं किसानों एवं पशुपालकों को सशक्त बनाने वाली हैं। बजट में आगामी दो वर्ष में शेष 2,500 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके लिए प्रावधानों में शिथिलन दिया जाएगा। साथ ही, नवीन 8 जिलों में क्रय-विक्रय सहकारी संघों की स्थापना की जाएगी। बड़ी संख्या में नई सहकारी समितियां खुलने से गांव-ढाणी स्तर तक सहकारिता का नेटवर्क मजबूत होगा। वहीं, वर्ष 2024-25 की उपलब्धियों की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राज्य के 70.21 लाख किसानों के बैंक खातों में 1 हजार 355 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है। इसी प्रकार, आदिनांक तक 30.43 लाख किसानों को 21 हजार 43 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया जा चुका है। प्रदेश में 95 हजार से अधिक नये किसानों को ऋण वितरित किया गया है। वहीं, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 28 हजार से अधिक गोपालक परिवारों को एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाया गया है।

होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

सुरज बंजारा
व्यवस्थापक

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World
सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है

भूपतसिंह राव
अध्यक्ष

मोटाराम
उपाध्यक्ष

एवं समस्त संचालक मण्डल सदस्य गण

आमथला वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड आमथला

हमारी सेवाएं : मिनी सहकारी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, अल्पकालीन फसली ऋण वितरण , खाद-बीज-कीटनाशक विक्रय

होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

किंवरली वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि. किंवरली

उम्मेदसिंह परमार
व्यवस्थापक

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World
सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है

केशरसिंह
अध्यक्ष

सरुपसिंह
उपाध्यक्ष

एवं समस्त संचालक मण्डल सदस्य गण

किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

हमारी सेवाएं : मिनी सहकारी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, अल्पकालीन फसली ऋण वितरण , खाद-बीज-कीटनाशक विक्रय

होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

नितोड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड नितोड़ा

किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

प्रतापराम
अध्यक्ष

भेराराम
उपाध्यक्ष

एवं समस्त संचालक मण्डल सदस्य गण

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World
सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है

दुर्गेश कुमार
व्यवस्थापक

हमारी सेवाएं : मिनी सहकारी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, अल्पकालीन फसली ऋण वितरण , खाद-बीज-कीटनाशक विक्रय

जालोर में अनूठी परंपरा का लोग उठाते हैं आनंद, सज-धजकर बाराती बनते हैं शहरवासी

होलिका दहन से पूर्व निकाली जाती है लोक देवता की बारात

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । होली का त्योंहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व का अपना एक अलग ही उत्साह रहता है। लोग होलिका दहन से पूर्व परंपरागत रूप से प्रहलाद की पूजा करते हैं और फिर होलिका दहन के समय परिक्रमा कर खुशहाली की कामना करते हैं। राजस्थान के अलग-अलग इलाकों में होली पर कई तरह की प्रथाओं का प्रचलन है। होली पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार 24 मार्च को फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाएगा। इसके अगले दिन यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को धुलंडी पर्व मनाया जाएगा। धुलंडी से ही सोलह दिन चलने वाली गणगौर पूजा का भी शुभारंभ होगा। इसमें होलिका दहन की राख से गणगौर की प्रतिमा बनाई जाती है, जिसकी सुहागिन महिलाएं सोलह दिन तक पूजा करेंगी। प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर होली पर्व पर कई तरह की परंपराओं का निर्वहन वर्षों से किया जाता रहा है। कहीं प्रहलाद की सवारी निकाली जाती है तो कहीं जुलूस निकाला जाता है। जालोर में लोक देवता की बारात निकलने की परंपरा है।

इलोजी महाराज की निकलती है बारात

दरअसल, जालोर में एक अनोखी बारात निकालने की परंपरा पिछले कई वर्षों से आज भी कायम है। यहां इलोजी महाराज (आनंद भैरूजी) की यह बारात नि काली जाती है। इसमें शहरवासी सजधज कर बाराती के रूप में शामिल होते हैं। लेकिन, जब तक बारात होली चौक पहुंचती है उसके पहले ही होलिका दहन कर लिया जाता है। ऐसे में वह शादी अधूरी मानी जाती है।

यूं होती है बारात की तैयारी

इस बारात में इलोजी महाराज (आनंद भैरू) के रूप में एक युवक को दुल्हा बनाया जाता है। दूल्हे को सजाकर घोड़ी पर बैठाया जाता है। शहरवासी साफा बांधकर बारात में शामिल होते हैं। ढोल व डीजे पर नाचते हुए यह बारात शहर के मुख्य इलाकों से होकर गुजरती है। दरअसल, इसके पीछे एक मान्यता जुड़ी है कि इलोजी लोक देवता हिरण्यकश्यप की बहन से प्रेम करते थे। एक तरफ तो शादी की तैयारी चल रही थी और दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को मारने की साजिश रच रहा था।

बारात पहुंचने से पहले होलिका दहन

हिरण्यकश्यप की साजिश के तहत उसने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद ली। भाई के कहने पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को जलाने के लिए उसे लेकर आग में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से आग में होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। ऐसे में इलोजी महाराज को रास्ते में होलिका की मौत की खबर मिलती है। इसके बाद वह जाकर अपनी पत्नी का जला हुआ शरीर देखते हैं और फिर उसकी राख को अपने शरीर पर लगाकर पूरे जीवन शादी नहीं करते। इसी मान्यता को लेकर आज भी जालोर में यह बारात निकाली जाती है। जालोर में कई वर्षों से बारात की अनोखी परंपरा चलती आ रही है।

घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें

सदस्यता फॉर्म

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं । समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है । अतः मुझे / हमें भी अंग्राकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें ।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 500/- ☐ दो वर्ष रु. 1000/- ☐ तीन वर्ष रु. 1500/- ☐ छह वर्ष रु. 3000/-

डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं ।

नाम / संस्था का नाम.....
ग्राम..... पोस्ट.....
तहसील..... जिला.....
फोन..... पिन कोड.....
राशि (रुपए) ..... बैंक का नाम.....

अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.

Bank Account Details : Name: Marwad ka Mitra A/C No.: 11134027554 IFSC Code: RMGB0000134
Google / Phonepay 9602473302

सदस्यता हेतु → Mo. 9602473302, Marwadkamitra.in

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र
संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा, तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041

प्रदेश के 100 जीर्ण- शीर्ण गोदाम भवनों का पुनर्निर्माण किया जाएगा - सहकारिता मंत्री

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। विधानसभा क्षेत्र चूरू में प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रावधानों के अंतर्गत सहकारी समितियों के नवीन गोदामों के निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में 500 मिलियन क्यूबिक फीट क्षमता के 100 एवं 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 नए गोदाम स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही प्रदेश के 100 जीर्ण-शीर्ण गोदाम भवनों को भी राज्य सरकार द्वारा पुनर्निर्मित किया जाएगा। सहकारिता मंत्री सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के गठन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप पूरे प्रदेश में 1 हजार से अधिक नवीन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार द्वारा विधानसभा क्षेत्र चूरू में प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का गठन कर दिया जाएगा। इससे पहले विधायक श्री हरलाल सहारण के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सहकारिता मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र चूरू में विगत पांच वर्षों में 11 सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति जारी की गई है। जिसका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र चूरू में संचालित 26 सहकारी समितियों के भवन व गोदाम विद्यमान हैं। जिसका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। उन्होंने जानकारी दी कि विधानसभा क्षेत्र चूरू में विगत पांच वर्षों में 1 सहकारी समिति (नाकरासर ग्राम सेवा सहकारी समिति) में भवन व गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। जिसमें गोदाम निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। जिसका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

समस्त किसान भाईयों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
जय सहकार जय सहकार जय सहकार
मडिया ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड मडिया
किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी
2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World
सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है
भगवतसिंह देवड़ा अध्यक्ष
हड़मतसिंह देवड़ा उपाध्यक्ष
एवं समस्त संचालक मण्डल सदस्य गण

मुकनसिंह देवल व्यवस्थापक
हमारी सेवाएं : मिनी सहकारी बैंक अल्पकालीन फसली ऋण वितरण, खाद-बीज कीटनाशक विक्रय

समस्त किसान भाईयों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
जानवी ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड जानवी
पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित व किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

लक्ष्मणराम पुरोहित व्यवस्थापक
2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World
सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है
ईश्वरसिंह अध्यक्ष
सवाईसिंह सहायक
एवं समस्त संचालक मण्डल सदस्य गण
हमारी सेवाएं : अल्पकालीन फसली ऋण वितरण, खाद-बीज कीटनाशक विक्रय

क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के लाभ में रहने पर ही कर्मचारियों को वेतनमान का लाभ - सहकारिता मंत्री

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। राज्य की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के लाभ में रहने पर नियमानुसार कर्मचारियों को वेतनमान का लाभ दिया जा सकता है। सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार ने विधानसभा में कहा कि सहकारी समितियां स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं। इनमें सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्तियां की जाती है तथा इनके अपने सेवा नियम हैं। उन्होंने जानकारी दी कि क्रय विक्रय सहकारी समितियों में विभिन्न वेतनमान लागू हैं। सहकारिता राज्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि समिति के स्थाई कर्मचारियों को वेतनमान का लाभ देने के लिए समितियों द्वारा कुछ शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है जैसे समिति द्वारा विगत 3 वर्षों में लाभ अर्जित किया गया हो, सदस्यों को नियमानुसार लाभांश का भुगतान किया गया हो तथा गठित कोषों में समिति द्वारा आवश्यक विनिधान कर दिया गया हो, कर्मचारियों को वेतनमान का लाभ दिए जाने के बाद भी संस्था हानि की स्थिति में न आये, समिति आगामी वर्षों में अपना व्यवसाय इस प्रकार बढ़ाए कि व्यवसाय में होने वाले लाभ इस व्यय हेतु पर्याप्त हो, इसके अतिरिक्त समिति द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यह वेतन संबंधी लाभ दिए जाने के बाद वेतन एवं प्रशासनिक व्यय वर्ष के सकल लाभ के 50 फीसदी से अधिक न हो। उन्होंने कहा कि इन शर्तों को पूरा करने के बाद प्रशासनिक स्वीकृति लेकर समितियों के स्थायी कर्मचारियों को वेतनमान का लाभ दिया जा सकता है। इससे पहले विधायक श्रीमती गीता बरवड के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सहकारिता राज्यमंत्री ने बताया कि क्रय विक्रय सहकारी समितियों में राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से चयनित कार्मिकों को संतोषप्रद परिवीक्षाकाल पूर्ण करने के उपरांत संबंधित समिति में लागू वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाता है। उन्होंने बताया कि राज्य की क्रय विक्रय सहकारी समितियों में समान रूप से वेतनमान लागू नहीं है।

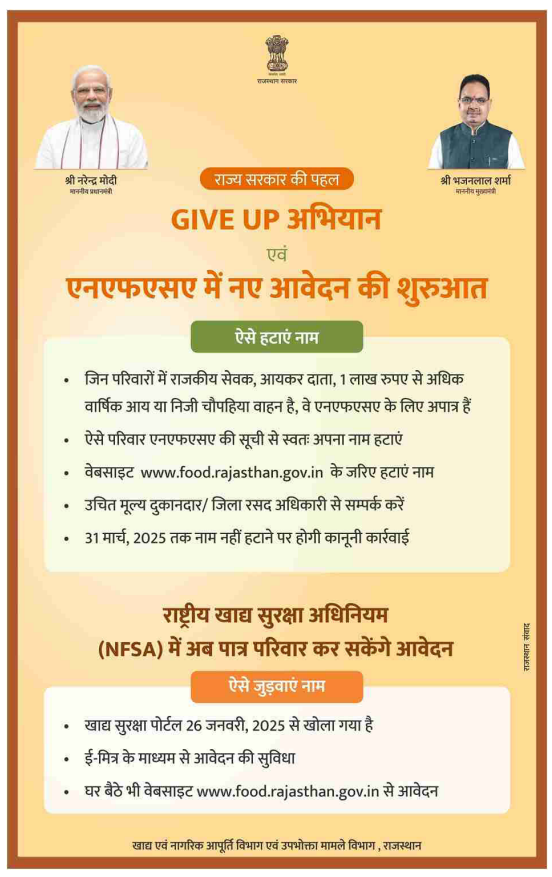

31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर अपात्र हटा सकेंगे अपना नाम

जालोर। रसद विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 'गिव-अप अभियान' के तहत योजना का लाभ स्वेच्छा से नहीं छोड़ने वाले 20 अपात्र परिवारों को 6 मार्च को वसूली नोटिस जारी किए गए हैं। जिले में अब तक वसूली के लिए 105 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। योजना 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी है। 31 मार्च तक त्याग नहीं करने वाले अपात्र लाभार्थियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जिला कलक्टर ने विभिन्न विभागों की ली समीक्षा बैठक

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर। जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 15वें वित्त आयोग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने 15वें वित्त आयोग व ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर आावश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग की बैठक में बालकों के प्रति हो रहे अपराधों की रोकथाम एवं संरक्षण के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की समीक्षा भी की। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदकिशोर राजोरा, उप पुलिस अधीक्षक गौतम जैन, बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक राजीव कुमार सुथार, किशोर गृह की अधीक्षक मौर कंवर आदि उपस्थित रहे।

समस्त किसान भाईयों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
लक्ष्मी ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड नारादरा
पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसायटी
श्रीमती उषा कंवर अध्यक्ष
मान सिंह उपाध्यक्ष
2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World
सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है
भोपाल सिंह राठौड़ व्यवस्थापक
तेजपाल सिंह देवड़ा सहा. व्यवस्थापक
हमारी सेवाएं
मिनी बैंक की मियादी जमाओं पर ब्याज दर देय सुविधा । अल्पावधि फसली सहकारी ऋण, भूमि की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत साख सीमा के तहत बायोमेट्रिक पद्धति से वितरित

जाबिया के प्रतिनिधिमंडल ने ली राज्य के सहकारी आन्दोलन और कार्यप्रणाली की जानकारी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। सहकारिता विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अंतर्गत प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में दि जयपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक प्रधान कार्यालय में जाम्बिया से आये प्रतिनिधिमंडल को बैंक की कार्यप्रणाली एवं राज्य में संचालित की जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई गई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडल अन्य देशों का दौरा कर वहां के सहकारी आन्दोलन तथा कार्यप्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं। इसी के तहत जाम्बिया का चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भारत के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल ने दि जयपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. के साथ ही अपेक्स बैंक, बीलवा ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं बड़ का बालाजी प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का भी दौरा कर कार्यप्रणाली को बारीकी से समझा। दि जयपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रधान कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को राज्य में सहकारी आन्दोलन को प्रभावी और सार्थक बनाने तथा विभिन्न सहकारी योजनाओं की आमजन तक पहुंच सुलभ कराने के उद्देश्य से किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी। साथ ही, योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रचार-प्रसार एवं प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जाम्बिया से आये प्रतिनिधिमंडल ने भी इस दौरान अपने देश के सहकारी आन्दोलन से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की। प्रतिनिधिमंडल ने भारत में 'सहकार से समृद्धि' के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। इस अवसर पर अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक श्री संजय पाठक, महाप्रबंधक श्री पी.के. नाग, दि जयपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक श्री दिनेश कुमार शर्मा एवं अधिशाषी अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

फसल बीमा योजना के तहत खरीफ एवं रबी की फसलों के कुल 2595.63 करोड़ रुपये की बीमा राशि वितरित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। उद्योग राज्य मंत्री श्री के.के. विश्नोई ने कृषि मंत्री की ओर से जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2023 और रबी 2023-24 की फसल बीमा दावा राशि का वितरण किया जा रहा है। रबी 2023-24 के लिए 1012.10 करोड़ रुपये की राशि किसानों को वितरित कर दी गई है, जबकि शेष राशि का भुगतान शीघ्र कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, खरीफ 2023 के लिए कुल 1583.53 करोड़ रुपये की राशि पात्र किसानों को वितरित कर दी गई है। शून्यकाल के दौरान, उद्योग राज्य मंत्री ने सदन के सदस्य श्री अजय सिंह द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए प्रश्न का उत्तर दिया । उन्होंने कहा कि नागौर (डीडवाना-कुचामन) सहित जिले के अविवादित फसल कटाई प्रयोग एवं फसल कटाई उपरांत होने वाले नुकसान के आधार पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के तहत खरीफ 2023 के लिए 1,91,735 पॉलिसीधारकों को कुल 207.56 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इसी प्रकार रबी 2023-24 के लिए 44,625 पॉलिसीधारकों को 52.19 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

कृषि फसलों के उत्पादन के द्वितीय अग्रिम अनुमान जारी किया

नई दिल्ली । कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2024-25 के लिए प्रमुख फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम आकलन जारी किया है। इसके अंतर्गत खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 1,664 लाख मीट्रिक टन रहने और रबी खाद्यान्न का उत्पादन 1,645 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। 2024-25 में 1,206 लाख मीट्रिक टन से अधिक खरीफ चावल के उत्पादन का अनुमान है, जो 2023-24 की तुलना में 1,132 लाख मीट्रिक टन अधिक है। वहीं, तूर दाल का उत्पादन 35.11 लाख मीट्रिक टन जबकि चने का उत्पादन 115.35 लाख मीट्रिक टन होने का आकलन किया गया है। प्रमुख फसलों की पैदावार के आंकड़े जारी करते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार कृषि क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता और प्रोत्साहन दे रही है जिसके नतीजे में फसलों के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है।

होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
ओड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड ओड़ा
किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी
तन सिंह -अध्यक्ष
खीव सिंह - उपाध्यक्ष
भोपाल सिंह - व्यवस्थापक
फूलाराम मेघवाल - सहायक
2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World
सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है

होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
आल्पा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड आल्पा
किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी
नरपत सिंह देवड़ा अध्यक्ष
गणेशाराम मीणा - उपाध्यक्ष
भरत कुमार मीणा व्यवस्थापक
2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World
सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है
हमारी सेवाएं : मिनी सहकारी बैंक अल्पकालीन फसली ऋण वितरण, खाद-बीज कीटनाशक विक्रय

नवाचारों को अपनाकर आगे बढ़ें सहकारी समितियां - जिला कलेक्टर

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बाड़मेर । केंद्रीय सहकारी बैंक के 66वें स्थापना दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अन्तर्गत सहकार से समृद्धि तथा पैक्स कम्प्यूटरीकरण की दिशा में ''गतिमान हमारा बैंक'' विषय पर पैक्स व्यवस्थापकों के लिए प्रशिक्षण व आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया । जिसको संबोधित करते हुए बैंक प्रशासक एवं जिला कलक्टर टीना डाबी ने कहा कि सहकारी समितियां तकनीकी के माध्यम से नवाचारों को अपनाकर कृषकों तथा सदस्यों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करें । उन्होने कहा कि पैक्स कम्प्यूटरीकरण एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिससे समितियों के तकनीकी उत्थान के साथ सहकार से समृद्धि में समिति स्तर पर जुड़े कृषकों व सदस्यों को तकनीकी सेवाओं का लाभ मिल सकेगा । वही पैक्स कम्प्यूटरीकरण कार्य को गति देकर 31 मार्च 2025 से पूर्व सभी पैक्स को गो-लाइव करवाकर सिस्टम ऑडिट पूर्ण करवाने के निर्देश बैंक प्रशासक ने कार्यशाला के दौरान प्रदान किए है। साथ ही राज्य सरकार की बजट घोषणा अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समितियों में बाजरा उत्पाद आउटलेट खोलने का आह्वान भी किया हैं । इस दौरान बैंक से सम्बद्ध कम्प्यूटरीकरण में गो-लाइव हो चुकी 78 पैक्स के व्यवस्थापक, टेक्नीकल टीम प्रतिनिधि, प्रबंधक दिनेश बंसल, लोकेश दाधीच, पूजा चौधरी, प्रिया शर्मा, आरती गोयल, नीलम, लीला जांगिड आदि उपस्थित थे।

राष्ट्रीय स्तर समितियों की सदस्यता लेने का आह्वान

कार्यशाला के दौरान सीसीबी प्रबंध निदेशक वासुदेव पालीवाल ने कहा संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मानाने का निर्णय लिया गया है जिसका ध्येय वाक्य थीम सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है रखा गया है । उन्होने व्यवस्थापकों को दैनिक डाटा एंट्री पूर्ण करने, सिस्टम ऑडिट करवाने, श्रीअन्न बाजरा के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए समिति स्तर पर श्रीअन्न आउटलेट खोलने के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की । साथ ही राज्य सरकार की सहकारी गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय स्तर की बीज, ऑर्गेनिक व एक्सपोर्ट समितियों की अधिक से अधिक सदस्यता लेने का आह्वान किया। इसके अलावा सीसीबी प्रबंध निदेशक ने सभी पैक्स व्यवस्थापकों को समितियों के कार्यों एवं कम्प्यूटरीकरण में हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया हैं ।

कम्प्यूटरीकरण एवं ऋण वसूली में अच्छा प्रदर्शन करने पर सम्मानित

आमुखीकरण कार्यशाला के दौरान जिले में पैक्स कम्प्यूटरीकरण एवं ऋण वसूली में अच्छा प्रदर्शन करने वाली खारा ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक हरिराम चौधरी, सेवनियाला ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक भंवराराम चौधरी, लापुन्दड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक सवाईराम चौधरी तथा आसोतरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक भट्टाराम मेगवाल को बैंक प्रशासक एवं जिला कलेक्टर सहित सीसीबी प्रबंध निदेशक द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया हैं ।

इन्होने रखे अपने विचार

कार्यशाला में निरीक्षक गोपाल सिंह ने गो-लाईव हो चुकी पैक्स को गो-लाइव के बाद की प्रक्रिया व 'ऑन-सिस्टम ऑडिट' पर जानकारी, तो सिस्टम इंटीग्रेटर अमित शर्मा ने तकनिकी पहुलओं पर जानकारी प्रदान की । वही बैंक अधिशाषी अधिकारी हरिराम पूनिया एवं मुख्य प्रबंधक अमराराम पटेल ने समितियों को डाटा एंट्री पूर्ण करने, अवधिपार ऋणों की वसूली करने, खरीफ ऋणों की मार्च समाप्ति से पूर्व वसूली करने, सहकार से समृद्धि अंतर्गत नवाचार करने का सुझाव दिया है तथा सवाऊ मूलराज ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक दिनेश कुमार की ओर से श्रीअन्न बाजरा के उत्पादों हेतु मिलेट्स उत्पाद आउटलेट्स खोलने की बात कही गई हैं ।

समस्त किसान भाईयों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
विरोल ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड विरोल
(पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित व किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी)

जैरुपाराम देवासी व्यवस्थापक
हमारी सेवाएं : अल्पकालीन फसली ऋण वितरण, खाद-बीज कीटनाशक विक्रय
जोगसिंह अध्यक्ष
2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World
सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है

मारवाड़ का मित्र

हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र
सांचौर (जिला-जालोर) शनिवार, 15 मार्च 2025
4

RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136
Post Reg No. R.J./SRO/9657/2023-25

किसान की ऋण सीमा के बराबर पहुंची ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन की हिस्सा राशि

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राज्य में 35 लाख किसानों को इस वित्तीय वर्ष में 25 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त योजना के तहत फसली ऋण बांटने की बजट घोषणा हुई हैं । साथ ही, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन से वंचित 2500 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नवीन जीएसएस का गठन भी किया जाएगा। जिसकी अनुपालना में हाल ही में सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय ने नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन हेतु निर्धारित मापदण्डों में संशोधन कर सामान्य क्षेत्र में सदस्यों से अमानत के तौर पर न्यूनतम 75 हजार एवं अनूसूचित जनजाति क्षेत्र में 50 हजार रुपए लेने के साथ नवगठित समिति की न्यूनतम सदस्य संख्या 150 तथा न्यूनतम हिस्सा राशि 1.50 लाख रुपए करने का प्रावधान किया हैं, इससे पूर्व यह हिस्सा राशि 3 लाख एवं सदस्य संख्या 300 थी । हालांकि प्रदेश में ब्याज मुक्त योजना के तहत अधिकतम 1.50 लाख तक का फसली सहकारी ऋण एक किसान को उसकी भूमि के आधार पर एमसीएल स्वीकृत कर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से मुहैया करवाया जाता है। गौरतलब हैं कि वर्ष 2022 से पूर्व न्यूनतम 500 सदस्य एवं 5 लाख की हिस्सा राशि पर ही नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाता था । लेकिन इसमें सरकार ने दो बार संशोधन कर वर्तमान समय में 150 सदस्य एवं 1.50 लाख की हिस्सा राशि का प्रावधान निर्धारित कर दिया है।

कार्यालय में समय में बंद पड़ा जालोर जिले की जैसावास जीएसएस मुख्यालय

इनका कहना हैं

सरकार को प्रदेश में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों को खोलने से पहले व्यवस्थापकों के रिक्त पदों को भरने के अलावा वर्तमान में कार्यशील पैक्स कर्मचारियों को बकाया वेतन भुगतान के मामले में कोई प्रावधान करना चाहिए, ताकि पैक्स का कुशल संचालन हो सकें और किसानों को नियमित सेवा भी मिल सकें।

***-हनुमानसिंह राजावत,** प्रांतीय अध्यक्ष राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन जयपुर*

3000 जीएसएस में व्यवस्थापक का पद खाली

पूर्ववर्ती सरकार के समय 300 सदस्य एवं 3 लाख की हिस्सा राशि का प्रावधान करने पर प्रदेश में क्रमशः 2000 से 2500 नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन हो गया । लेकिन इन जीएसएस में कार्य करने के लिए मानव संसाधन के कोई प्रावधान नहीं किए गए, जबकि प्रदेश की 8500 में से लगभग 3000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक का पद रिक्त हैं और कर्मचारियों की कमी का आलम यह हैं कि एक-एक व्यवस्थापक के पास तीन से पांच जीएसएस का चार्ज हैं । इन्ही व्यवस्थापकों को सीसीबी के कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक का पदभार भी मिला हुआ है।

खाद्य सुरक्षा योजना के तहत खाद्यान्न वितरण की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई

जालोर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत जिले में फरवरी माह में खाद्यान्न वितरण की अवधि को 10 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च तक किया गया है। जिला रसद अधिकारी एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी आलोक झरवाल ने बताया कि फरवरी माह में आवंटित खाद्यान्न तकनीकी समस्याओं के कारण पूर्ण रूप से वितरण नहीं हो पाया था। ऐसे में जनहित को ध्यान में रखते हुए माह फरवरी, 2025 के अवशेष/अवितरित खाद्यान्न वितरण करने की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई गई है जिसमें फरवरी माह के खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।

होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

सरवाना ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड सरवाना

किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

राणाराम पुरोहित
अध्यक्ष

भावेश कुमार
स. व्यवस्थापक

एवं समस्त संचालक मण्डल सदस्य गण

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World
सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है

लक्ष्मणराम पुरोहित
व्यवस्थापक

हमारी सेवाएं : अल्पकालीन फसली ऋण वितरण
राशन वितरण- खाद-बीज-कीटनाशक विक्रय

निर्धारित तिथि तक शत-प्रतिशत ऋण वसूली के निर्देश

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बाड़मेर । जिले में किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा खरीफ 2024 में वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों की चुकारा करने की निर्धारित तिथि 31 मार्च 2025 के चलते सीसीबी प्रबंध निदेशक वासुदेव पालीवाल ने समस्त शाखा प्रबन्धक, सहायक अधिशासी अधिकारी, कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक को पत्र लिखा हैं, जिसमें मार्च माह में तीन सप्ताह का समय वसूली कार्य के लिए शेष बताते हुए शाखा कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यरत ग्राम सेवा सहकारी समितियों की समितिवार बकाया राशि की समीक्षा कर वसूली कार्य योजना बनाने के साथ संबंधित व्यवस्थापक को शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही, पत्र के जरिए बताया कि ऋणी कृषक देय तिथि अथवा उससे पूर्व ऋण का चुकारा कर शुन्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन फसली ऋण योजना का लाभ प्राप्त कर सकतें हैं, अन्यथा देय तिथि तक ऋण का चुकारा नही करने पर ऋण राशि अवधिपार श्रेणी में वर्गीकृत हो जाएगी।

समस्त ग्रामवासियों को रंगोत्सव के पावन पर्व होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

एक सब के लिए, सब एक के लिए

सोरड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड सोरड़ा

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसायटी

दानाराम चौधरी
अध्यक्ष

नारायणलाल राणा
व्यवस्थापक

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World
सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है

गणेशाराम
उपाध्यक्ष
रुड़ाराम देवासी
सहा. व्यवस्थापक
एवं समस्त संचालक मण्डल सदस्य गण

किसान सम्मान निधि के तहत अनुचित लाभ लेने वाले अपात्र व्यक्तियों से वसूली की कार्यवाही जल्द - सहकारिता राज्यमंत्री

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अनुचित लाभ लेने वाले अपात्र व्यक्तियों से निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर शीघ्र वसूली की जाएगी। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने विधानसभा में कहा कि पाली जिले में किसान सम्मान निधि के तहत अनुचित तरीके से राशि हस्तांतरण किये जाने के प्रकरण की जाँच के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग को नियुक्त किया गया है। जाँच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सहकारिता राज्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के प्रारंभ में कृषक द्वारा दिए गए घोषणा पत्र के आधार पर ही लाभ राशि का हस्तांतरण कर दिया जाता था। बाद में भूमि की रिपोर्ट अपलोड करना भी अनिवार्य किया गया। केंद्र सरकार द्वारा भी अपात्र व्यक्तियों से सम्मान निधि की राशि वसूलने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच पाली में अपात्र व्यक्तियों को दिए गए लाभ के प्रकरण संज्ञान में आने के बाद पाली जिला कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार देसूरी, मारवाड़ जंक्शन और रानी में एफआईआर दर्ज करवाई गयी है। इससे पहले विधायक श्री केसाराम चौधरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत कुल 13 हजार 858 अपात्र व्यक्तियों के आवेदन पंजीकृत हैं, जिन्हें योजना के तहत विभिन्न किश्तों के माध्यम से 826.66 लाख राशि का लाभ प्राप्त हुआ है। उन्होंने इन अपात्र व्यक्तियों को की गयी हस्तान्तरित राशि का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि इन 13 हजार 858 अपात्र व्यक्तियों में से 13 हजार 720 व्यक्तियों के नाम ऐसे हैं, जो उन गांवों के निवासी नहीं हैं। इस प्रकरण की जांच के लिए जिला कलेक्टर, पाली को निर्देशित किया गया है। अपात्र कृषकों को पात्र किया जाकर लाभ दिये जाने के सम्पूर्ण प्रकरण की जांच उपरान्त उत्तरदायी पाये गये कार्मिकों एवं अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

लूणोल ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड लूणोल

किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

देवीलाल
अध्यक्ष

एवं समस्त संचालक मण्डल सदस्य गण

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World
सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है

लाखाराम
व्यवस्थापक

हमारी सेवाएं : अल्पकालीन फसली ऋण वितरण
राशन वितरण- खाद-बीज-कीटनाशक विक्रय

होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

सांगाणा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड सांगाणा

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत, किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

नरपत सिंह
अध्यक्ष

कादर खाँ
उपाध्यक्ष

एवं समस्त संचालक मण्डल सदस्य गण

वालाराम
व्यवस्थापक

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World
सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है

हमारी सेवाएं : अल्पकालीन फसली ऋण वितरण - राशन वितरण- खाद-बीज-कीटनाशक विक्रय

ऑडिट कार्य में लापरवाही बरतने पर 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को पैनल से हटाया

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । सहकारिता विभाग में ऑडिट कार्य में लापरवाही बरतने पर 6 चार्टर्ड अकाउन्टेंट फर्मों को वर्तमान गठित पैनल से हटाते हुए भविष्य में गठित किए जाने वाले पैनल में शामिल करने पर रोक लगाई गई है। इसके लिए सहकारिता विभाग पंजीयक श्रीमती मंजू राजपाल द्वारा इस सम्बन्ध में एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है। जिसके मुताबिक, श्रीगंगानगर जिले की श्रीविजयनगर तहसील अंतर्गत 2जीबीए ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. 3 जीबी में गबन एवं अनियमितता का प्रकरण संज्ञान में आया था। प्रकरण में प्रबंध निदेशक केन्द्रीय सहकारी बैंक गंगानगर के आदेश पर मुख्य प्रबंधक, जीकेएसबी श्रीगंगानगर द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 के तहत जांच की गई थी। जांच परिणाम एवं निर्देश में समिति में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 तक ऑडिट कार्य में उक्त चार्टेड अकाउन्टेंट फर्मों की लापरवाही सामने आने पर, जांच परिणाम के आधार पर कार्यवाही करते हुए मै. विभोर रूपेश एण्ड कम्पनी, मै. रतन गर्ग एण्ड एसोसिएट्स, मै. गोयल नागपाल एण्ड कम्पनी, मै. राकेश लालगढ़िया एण्ड एसोसिएट्स, मै. भरत मून्दड़ा एण्ड कम्पनी एवं देवेन्द्र भटेजा एण्ड कम्पनी को सहकारी सोसायटियों की लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान गठित पैनल से हटाते हुए भविष्य में गठित किए जाने वाले पैनल में शामिल करने पर रोक लगाई गई है।

होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

लापोद ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड लापोद

किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

कपूराराम
अध्यक्ष

देवी सिंह मेडतीया
उपाध्यक्ष

एवं समस्त संचालक मण्डल सदस्य गण

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World
सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है

मदनलाल
व्यवस्थापक

हमारी सेवाएं : अल्पकालीन फसली ऋण वितरण
राशन वितरण- खाद-बीज-कीटनाशक विक्रय

मारवाड़ का मित्र हिन्दी पाक्षिक

विज्ञापन एवं समाचारों के लिए संपर्क करें

:: Website ::
Www.Marwadkamitra.in

दो साल से तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान पेटे स्वीकृत नहीं हो पाई राशि

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित होने वाले अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा करने की एवज में देय 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान की राशि भारत सरकार स्तर से पिछले दो सालों से स्वीकृत नहीं हो पाई है। दरअसल, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ब्याज अनुदान को लेकर मांगी गई सूचना के क्रम में यह जानकारी उपलब्ध कराई है। साथ ही, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी एवं नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. राजीव सिवाच द्वारा आरटीआई आवेदन में दी गई जानकारी के अनुसार, राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को अल्पकालीन फसली ऋण वसूली में देय 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में आरएससीबी यानि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक को 2,28,94,10,409.00 रुपए वही वित्तीय वर्ष 2019-20 में आरएससीबी को 1,13,12,49,823.00 रुपए एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में आरएससीबी को 2,52,18,90,346.00 रुपए तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में आरएससीबी को 2,85,3-9,48,932.00 रुपए की राशि जारी की गई । इसके अलावा आरटीआई के जवाब में बताया गया कि वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 से संबंधित जानकारी भारत सरकार से राशि स्वीकृत होने के बाद ही उपलब्ध कराई जाएगी ।

RIGHT TO INFORMATION

माइक्रो एटीएम मॉडल को नाबार्ड देश के हर जिले तक पहुंचाए -शाह

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली । डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला का उद्घाटन कर केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आज जब हम श्वेत क्रांति-2 की तरफ बढ़ रहे हैं तब सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी का महत्व बहुत बढ़ जाता है, श्वेत क्रांति-1 से अब तक जो हमने हासिल किया है उससे सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी को पूरा करना अभी बाकी है। उन्होने कहा कि श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य लक्ष्य सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी है और श्वेत क्रांति-2 की शुरूआत से ही इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 10 साल में देश में खेती में खुशहाली की एक अच्छी शुरूआत हुई है। उन्होंने कहा कि गांव से ग्लोबल तक जाने का हौंसला भी बढ़ा है और पद्धतियां भी बनी हैं और को-ऑपरेटिव के माध्यम से समूह से सफलता पाने का विश्वास भी बढ़ रहा है। श्री शाह ने कहा कि अब समय आ गया है कि फार्म से फैक्ट्री तक की पूरी चेन ग्रामीण क्षेत्र में ही हो। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सहकार से शक्ति, सहकार से सहयोग और सहकार से समृद्धि के तीन सूत्रों के साथ-साथ पीपल फॉर पीपल के मंत्र चरितार्थ कर रही है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज देश में 23 राज्यस्तरीय संघ हैं लेकिन हमें श्वेत क्रांति 2.0 के तहत हर राज्य में एक राज्य स्तरीय संघ और देश के 80 प्रतिशत जिलों में दुग्ध संघ बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान की 28 विपणन डेयरियों की संख्या बढ़ाकर 3 गुना कर सकते हैं। श्री शाह ने कहा कि कोऑपरेटिव डेयरी क्षेत्र में उपभोक्ता के पास से आने वाले पैसे में से 75 प्रतिशत से अधिक किसानों को वापस मिलता है। उन्होंने कहा कि कॉपरेरिट सेक्टर में किसानों को 32 प्रतिशत पैसा वापस मिलता है। उन्होंने कहा कि हमें देश के हर किसान के लिए इस अंतर को कम करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसके साथ ही, 16 करोड़ टन गोबर को हमारे कोऑपरेटिव के नेट में लाने का भी प्रयास करना चाहिए। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि जैविक खाद का शत-प्रतिशत दोहन करने के लिए ज़िला स्तर के दुग्ध संघों और ग्रामीण डेयरियों को उन किसानों को भी सहकारिता के नेट में लाना होगा जो अभी कोऑपरेटिव से नहीं जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि कई किसान प्राइवेट डेयरी को दूध देते हैं, लेकिन उनके गोबर का प्रबंधन सहकारिता क्षेत्र को करना चाहिए, जिससे हमारी मिनिमम वायबिलिटी की समस्या दूर होगी और प्राइवेट सेक्टर की ओर जा रहे किसान को सहकारिता क्षेत्र की ओर आकर्षित करने में सफलता मिलेगी। श्री शाह ने कहा कि गैस उत्पादन के क्षेत्र के सफल प्रयोगों को 2 साल के लक्ष्य साथ 250 जिला दुग्ध उत्पादक संघों में मॉडल के रूप में सफलतापूर्वक लागू करने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, प्रोफेसर एस. पी. सिंह बघेल एवं श्री जॉर्ज कुरियन, श्रीमती अलका उपाध्याय, सचिव, मत्स्यपालन, सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।

कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर में 72 प्रतिशत महिलाएं कर रही काम

श्री अमित शाह ने कहा कि मीथेन और कार्बनडाइऑक्साइड के उत्सर्जन में बहुत कमी आई है और इसका सौ प्रतिशत कार्बन क्रेडिट किसानों के बैंक खाते में जाना चाहिए और यही सर्कुलरिटी का असली मतलब है। उन्होंने कहा कि डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर महिलाओं को रोजगार देने के मामले में भी बहुत काम करता है और आज कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर में 72 प्रतिशत महिलाएं काम कर रही है। श्री शाह ने कहा कि इससे सिद्ध होता है कि कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर में माताओं बहनों के रोजगार और उनके सशक्तिकरण पर काम होता है।

होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं

चुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड चुरा

पंचायत समिति - जालोर, जिला - जालोर

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World
सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है

किसानों, ग्रामीणों व सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

नरेन्द्रसिंह बालावत
अध्यक्ष

हेमसिंह राठौड
उपाध्यक्ष

नारायणसिंह बालोत
व्यवस्थापक

हमारी सेवाएं : मिनी सहकारी बैंक - अल्पकालीन फसली ऋण वितरण - खाद-बीज कीटनाशक विक्रय

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक एवं मुद्रक प्रकाश वैष्णव द्वारा वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स, वैष्णव फार्म पसावा तह. चितलवाना जिला-जालोर (राज.) 343041 से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर (जिला-जालोर) से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत ख़बर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।